The visit to Japan has helped in generating a better understanding among Japanese officials and businessmen regarding the favourable climate in India for investment and technology transfer, especially in high-tech. areas. There is also now a greater appreciation in Japan of the steps taken by Govt. to rationalise policies and streamline and simplify procedures.

Oil and gas found in Rajasthan

3210. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Oil India Limited has found oil/gas in the desert sands of Rajasthan;

(b) if so, what is the quantum of gas/oil found;

(c) what is the exact location where the oil has been struck; and

(d) whether any efforts are being made to explore the oil?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) Oil India Limited has discovered gas in the first exploratory well drilled at Tanot in Western Rajasthan on 7-9 August, 1988.

(b) During the production testing carried out on 7—9-8-1988, the well produced gas at a steady rate of 45,000 standard cubic metres per day through 6 mm bean.

(c) The location of the well at Tanot where gas has been struck is about 145 Kms. from Jaisalmer towards North-West.

(d) Oil India Ltd. will drill additional wells in this area for discovery/production of crude oil/natural gas.

Shortage of Acetaldehyde

3211. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a market survey has forecast a shortage of acetaldehyde in the coming years which may adversely affect production of glyoxal and bulk drugs; and

(b) if so, what are the main reasons for the same and what steps are being taken to see that the shortage does not affect the production of bulk drugs?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) No market survey has been made. However, neither any shortage of acetaldehyde has been reported nor is it anticipated in the near future.

Industrial plots at Patparganj, Delhi

3212. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Administration had received a lot of applications for the allotment of industrial plots at Patparganj;

(b) if so, what was the total number of plots that were sold, and at what rates the plots were sold;

(c) whether these plots were allotted by draw of lots or by bids; and

(d) to what extent Government have benefited?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) According to Delhi Administration about 500 plots are proposed to be allotted on lease basis at a premium of Rs. 500/- per sq. mtr. as soon as the criteria for allotment are finalised.

जन जातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने संबंधी उपाय

3213. **श्री अजीत जोगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन जातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने और इन उद्योगों को इसी प्रकार के अन्य आधुनिक उद्योगों की तुलना

में आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ;

(ख) सरकार हस्तशिल्प पर आधारित कुटीर उद्योगों और भारत और विदेशों में इनके उत्पादों की बिक्री हेतु मंडियां तलाश करने के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन देगी ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने लिए कि इन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपयुक्त दरों पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) परम्परागत उद्योगों सहित, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार रियायती वित्त कच्चा-माल तथा प्रशिक्षण संबंधी सहायता आदि देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में मदद करती है। हस्त-शिल्प के क्षेत्र में चालू योजनायें मिश्रित स्वरूप की हैं। और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई विशेष अभ्युपाय की परिकल्पना नहीं की गयी है। तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिकता रूप से जोर दिया जाता है। इसी प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को अवसर उपलब्ध कराने पर बल देते हुए स्थानीय संसाधनों व स्थानीय दक्षता का इस्तेमाल करते हुए उद्योगों के विकास की ओर उन्मुख है।

(ख) और (ग) हस्तशिल्प पर आधारित उद्योगो की विपणन आवश्यकताओं के संबंध में "विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्रों" के नाम से जाने जाने वाले संगठनों की एक श्रृंखला द्वारा काफी हद तक ध्यान किया गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास उत्पादों का विपणन बढ़ाने के लिए देश में बहुत बड़ी संख्या में बिक्री केन्द्र हैं। विदेशी बाजारों में बाजार सम्भावना का पता करने में हस्तशिल्प उद्योगों के सहायतार्थ निम्नलिखित संवर्धनात्मक अभ्युपाय भी किये गये हैं :-

(1) विदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाता है जिसके लिये बाजार विकास सहायता उपलब्ध है ;

(2) निर्यात संभावना का पता करने के लिए समय-2 पर बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित किए जाते है ;

(3) तकनीकी शिष्ट मंडल/विशेषज्ञों को उत्पाद तकनीकों के बारे में अध्ययन करनेहेतु विदेशों को भेजा जाता है ताकि विदेशी बाजारों में व्यापक रूप से स्वीकार करने के लिए उत्पाद-गुणवत्ता में सुधार किया जा सके ।

राज्य हस्तलिप विकास निगमों को कच्चे माल की नियमित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल के डिपो स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता दी गयी हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग यथासभव अपने सहायता प्राप्त अभिकरणो को उचित दरों पर कच्चे माल की आपूर्ति कराने में भी सहायता प्रदान करता है ।

Nomination of directors on the Board of Managment of the Peerless General Finance and investment company Limited

3214. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Calcutta High Court has in a recent judgement upheld the petition of the Peerless General Finance and Investment Company against a decision of the Company Law Board to nominate four Directors on the Board of Management of the Peerless under section 408 of the Companies Act, 1956; and